1462 लोगों को रखा गया तीनों सेनाओं की विभिन्न क्वारंटाइन सुविधाओं में। इनमें से 389 को घर भेजा जा चुका है। 1073 लोगों की देखभाल मानेसर, हिंडन, जैसेलमेर, जोधपुर और मुंबई के केंद्रों में की जा रही है।

सोनिया ने प्रधानमंत्री से कहा, कोरोना से जंग में साथ हैं हम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले का पूरा समर्थन करने की घोषणा की है। सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा देते हुए देश में अधिक संख्या में अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करने और कोरोना के इलाज में लगे चिकित्साकर्मियों को विशेष मदद देने का सुझाव भी दिया है। वहीं लॉकडाउन से प्रभावित कमजोर वर्गों के साथ वेतनभोगी और कारोबार क्षेत्र के लोगों को राहत पैकेज देने का पीएम से अनुरोध किया है।

सोनिया ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी ने देश में चिंता, डर और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न कर दिया है। इसने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। कोरोना को रोकने और हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है। उन्होंने लिखा है कि 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं। महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र

- संकट से प्रभावित मजदूरों, किसानों और कामगारों को विशेष मदद का किया अनुरोध
- इलाज में जुटे चिकित्साकर्मियों को छह महीने तक विशेष भत्ते देने का दिया सुझाव

सोनिया गांधी। (फाइल)

सोनिया ने यह भी कहा है कि कोरोना संकट ने सभी वर्गों को प्रभावित किया है। खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं दैनिक जीवन पर इसका प्रतिकूल असर हुआ है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ का जो आवंटन किया है, उसके तहत चिकित्साकर्मियों को जरूरी मास्क, बॉडीशूट और पर्सनल प्रोटेक्शन तत्काल मुहैया कराया जाए। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों-नर्सों को प्रोत्साहन के तौर पर मार्च से लेकर अगले छह महीने तक 'स्पेशल रिस्क अलाउंस' दिया जाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना से जुड़ी सभी सूचना और आवश्यक जानकारी देने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल होना चाहिए।

सोनिया ने कहा है कि दुनिया के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा वाले देशों की व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में सरकार को फौरन अस्थायी अस्पताल की सुविधाओं का निर्माण शुरू करना चाहिए, जिनमें बड़ी संख्या में आइसीयू एवं वेंटिलेटर हों। प्रधानमंत्री से उन्होंने कोरोना की बंदी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित दैनिक मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, कंस्ट्रक्शन एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, मछुआरे और खेतिहर मजदूरों के साथ किसानों को आर्थिक मदद सीधे खाते में देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा है कि रबी सीजन को देखते हुए एमएसपी किसानों को मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए। किसानों की कर्ज अदायगी छह महीने रोकी जाए।

सोनिया ने कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित 'न्याय योजना' यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करने पर भी गौर करने की सलाह दी है। इसी तरह कर्मचारियों की छंटनी रोकने और वेतनभोगी लोगों को मदद देने का अनुरोध करते हुए छह महीने तक बैंकों की ईएमआइ की अदायगी रोकने का आग्रह किया है। इन छह महीनों का ब्याज भी माफ करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सभी व्यवसायों खासकर माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्री के लिए भी विशेष पैकेज की जरूरत बताई है।

राहुल गांधी बोले-सही दिशा में पहला कदम

नई दिल्ली, एजेंसियां : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट से प्रभावित गरीब लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे सही दिशा में उठाया गया पहला कदम बताया है। गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार की ओर से वित्तीय पैकेज की घोषणा सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर उसके किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं और बुजुर्गों का कर्ज है, जिन्हें मौजूदा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन से होने वाली परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस आर्थिक पैकेज की मांग करती रही है।

राहुल गांधी। (फाइल)

इस बीच, कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वे जमीन पर उतरें और जरूरतमंद लोगों को खाद्य वस्तुओं के पैकेट और जरूरी दवाएं वितरित करें। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और सांसदों को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि संकट के इस समय में वे लोगों की हरसंभव मदद करें। इस पत्र में वेणुगोपाल ने कहा है कि इस निर्णायक समय में लोगों तक जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने राज्यों में प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जरूरतमंद लोगों को खाने-पीने की वस्तुओं के पैकेट और जरूरी दवाएं वितरित करें।

भारत ने पाक से किया सिंधु आयुक्तों की बैठक टालने का अनुरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने पाकिस्तान से कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सिंधु आयुक्तों की बैठक टालने का अनुरोध किया है। हालांकि, भारत के इस अनुरोध पर पाकिस्तान ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों देशों के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार, हर साल 31 मार्च को सिंधु आयुक्तों की बैठक होती है। साल में कम-से-कम एक बार यह बैठक भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित की जाती है। सिंधु आयुक्तों की पिछली बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 13 फरवरी को भारत के सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह के सामने मार्च के दूसरे पखवाड़े में बैठक करने का प्रस्ताव रखा था। 12 मार्च को मेहर अली शाह ने सक्सेना का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा था कि एजेंडे का विस्तृत विवरण निर्धारित समय पर तय कर लिया जाएगा। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद भारत ने दोनों देशों के व्यापक हितों को देखते हुए कुछ समय के लिए बैठक टालने का अनुरोध किया है।

वायरस के खिलाफ रक्षा तैयारियों पर नजर

मुकाबला ▶ कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा की

सिविल एजेंसियों को हरसंभव मदद देने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, प्रेट्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य सैन्य संगठनों से कहा है कि वह वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुकाबले के लिए नागरिक प्राधिकरणों को हरसंभव सहायता प्रदान करें।

रक्षा मंत्री ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए रक्षा मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा की है। भारत में विगत मंगलवार की मध्यरात्रि से 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 600 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेश से भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशियों को सुरक्षित निकालने और फिर उनके लिए क्वारंटाइन फैसिल्टी तैयारी करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सशस्त्र बलों और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वह नागरिक प्रशासन को हर स्तर पर सहायता मुहैया कराएं। रक्षा मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों ने अहम भूमिका निभाई है। डीआरडीओ की लैब ने 20 हजार लीटर सैनिटाइजर बनाकर दिल्ली पुलिस को दस हजार लीटर समेत विभिन्न एजेंसियों को इसकी आपूर्ति की है। रक्षा विकास अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 10 हजार मास्क की आपूर्ति भी दिल्ली पुलिस के अफसरों को की है। वह कुछ निजी कंपनियों के साथ मिलकर कर्मचारियों की सुरक्षा के उपकरण जैसे बॉडी सूट और वेंटिलेटर आदि भी बनाने पर काम कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) ने सैनिटाइजर, मास्क और बॉडी सूट बनाने का बीड़ा उठाया है तो डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड वेंटिलेटर बनाने में जुटा हुआ है।

कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के एक्शन प्लान को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरनल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एएनआइ

बैठक में अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को सशस्त्र सेनाओं की ओर से अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया। भारतीय वायुसेना ने भी कई अहम कदम उठाए हैं और भारतीय नागरिकों को चीन, जापान और ईरान जैसे देशों से सुरक्षित वापस लाने का काम किया है। तीनों सेनाओं की विभिन्न क्वारंटाइन सुविधाओं में 1462 लोगों को रखा गया। इनमें से 389 को घर भेजा जा चुका है। 1073 लोगों की देखभाल मानेसर, हिंडन, जैसेलमेर, जोधपुर और मुंबई के केंद्रों में की जा रही है। 950 लोगों के लिए अतिरिक्त क्वारंटाइन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री के अलावा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवाने, रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार और डीआरडीओ चैयरमैन जी. सतीश रेड्डी मौजूद थे।

जावडेकर ने अफसरों से कहा- मस्त रहें, व्यस्त रहें

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने तीनों मंत्रालयों के अफसरों के साथ गुरुवार को ऑडियो कांफ्रेंसिंग की और लॉकडाउन के दौरान 'मस्त रहें, व्यस्त रहें' की सलाह दी। उनके पास सूचना प्रसारण, पर्यावरण तथा भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालयों का प्रभार है।

जावडेकर ने हैशटैग 21 डेजचैलेंज व इंडिया फाइट कोरोना के साथ ट्वीट किया, 'ऑडियो ब्रिज के माध्यम से मैंने अपने तीनों मंत्रालयों के 400 अफसरों से संवाद किया। उनसे घर पर रहने, सकारात्मक बने रहने, व्यस्त व मस्त रहने को कहा। इसके अलावा भी कई गतिविधियों की सलाह दी।' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें अगले 20 दिनों के लिए कार्य सूची बनाने को कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों मंत्रालय के अधिकारी सभी अहम काम पूरे कर लेंगे।' इस बीच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अफसरों को 24 घंटे उपलब्ध रहने को कहा है। पीआइबी ने ट्वीट किया, 'कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के समय में मीडिया और संचार आवश्यक सेवा हैं। मंत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने और पहले से भी ज्यादा काम करने का सुझाव दिया है, ताकि लोगों तक सही और पुष्ट जानकारी पहुंच सके।'

काबुल आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के संपर्क में है भारत : विदेश मंत्री

- गुरुद्वारे पर बुधवार को हुए आइएस के आतंकी हमले में गई थी 25 की जान
- अफगानिस्तान में भारत के राजदूत विनय कुमार ने पीड़ितों से की मुलाकात

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार गुरुद्वारे पर आतंकवादी हमले में मारी गई मां के ताबूत के पास बिलखती बच्ची। हमले में मारे गए लोगों का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। यह दृश्य झकझोर देने वाला था। रायटर

नई दिल्ली, प्रेट्र : काबुल स्थित भारतीय उच्चायोग अफगानिस्तान की राजधानी में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यह बात कही। बुधवार को काबुल स्थित गुरुद्वारे पर बंदूकधारियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोग मारे गए थे। मृतकों में एक पुरानी दिल्ली निवासी 71 वर्षीय तियान सिंह हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए हाल ही में ऐतिहासिक समझौता किया है।

विदेश मंत्री ने ट्वीट किया,'आतंकी हमले से उत्पन्न आक्रोश और दुख को समझता हूं। भारतीय उच्चायोग तियान सिंह के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए काम कर रहा है।' अफगानिस्तान में भारत के राजदूत विनय कुमार ने गुरुवार को हमले से पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। उन्होंने घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि हम इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत इस घड़ी में अफगानिस्तान में प्रभावित हिंदू एवं सिख समुदाय के परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने को तत्पर है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप के बीच अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक पूजास्थल पर ऐसा कायराना हमला इन हमलावरों एवं उनका समर्थन करने वालों की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों के पराक्रम, उनके साहस और समर्पण की सराहना करते हैं। अफगानिस्तान में शांति एवं सुरक्षा के वातावरण के प्रयासों में भारत वहां के लोगों, सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है।

यूएन ने की हमले की निंदा : गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने निंदा की है। साथ ही कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में धार्मिक स्थलों पर आम लोगों को निशाना बनाने जैसे कृत्य का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि महासचिव ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका ने भी हमले की आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा कि आइएस और अन्य आतंकी संगठनों से मुक्त भविष्य अफगानिस्तान के लोगों का हक है। उन्हें राजनीतिक समझौते पर बात करने के लिए आगे आने और आतंकी संगठनों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत है।

डब्लूएचओ को मजबूत बनाने की जरूरत : मोदी

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) जैसे संस्थानों के ढांचे में आमूल चूल बदलाव की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डब्लूएचओ को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह के हालात पैदा होने पर यह निर्णायक फैसला कर सकें। खास तौर पर यह भी देखा जाए कि किस तरह से ऐसी स्थिति की समय से पहले पहचान की जा सके व दूसरे देशों को आगाह किया जा सकेगा। जब कोरोना वायरस का टीका विकसित किया जाए तो उसे सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सके। सनद रहे कि कोरोना महामारी को लेकर कई लोग डब्लूएचओ की काफी आलोचना कर रहे हैं कि वह इसके उत्पन्न होने पर चेतावनी नहीं जारी कर सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी डब्लूएचओ की आलोचना की है।

तकनीकी खामी के चलते एक-दो नेता भाषण नहीं दे सके : जी-20 देशों की यह बैठक इस मायने में भी खास रही कि पहली बार दुनिया के शीर्ष 20 शक्तिशाली देशों के प्रमुखों की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई है। तकनीकी खामी की वजह से एक-दो नेता संबोधन नहीं दे सके। यह संगठन वर्ष 2007-08 के वैश्विक मंदी के दौरान सामने इसलिए आया था कि दुनिया के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके। लेकिन गुरुवार को हुई बैठक में यह तय हुआ कि आगे स्वास्थ्य व अन्य मानवीय पहलुओं से उपजी चुनौतियों पर भी इस समूह की बैठक हुआ करेगी। कोरोना वायरस से अभी दुनिया में जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनमें से 90 फीसद समूह 20 देशों के ही नागरिक हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि बैठक में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये गये जैसा कि उम्मीद थी बल्कि सभी पक्षों ने एक सामूहिक सहयोग की मिसाल पेश करने की कोशिश की। वैसे पीएम मोदी ने इस बैठक में सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के विकासशील, अविकसित या गरीब समेत उन सभी देशों का पक्ष रखने की कोशिश की जो इस समूह का हिस्सा नहीं है।

केंद्रीय मंत्रियों को बनाया राज्यों का प्रभारी

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय मंत्रियों को अपने-अपने राज्यों का प्रभार संभालने और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए कहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से सभी मंत्रियों को पत्र भेजे गए हैं।

एक मंत्री ने बताया, 'निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि गरीबों और वंचितों को भोजन मिले, उनके इलाकों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत संचालित दुकानों में राशन खत्म न हो, स्थानीय बाजारों में जरूरी सामान उपलब्ध रहे और लोगों से उन वस्तुओं के लिए ज्यादा मूल्य न लिया जाए।' एक सूत्र ने मंत्रियों को लिखे गए पत्र का विवरण देते हुए कहा, 'स्थानीय जिलाधिकारी के साथ संपर्क में रहें, सुनिश्चित करें कि जो लोग भी विदेश से लौटे हैं वे क्वारंटाइन नियमों का पालन करें और उन लोगों के आंकड़ें रखें जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हुई है।' मंत्रियों से इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा गया है।

इन मंत्रियों को बनाया प्रभारी : केंद्रीय मंत्रियों में मुख्तार अब्बास नकवी को

मुख्तार अब्बास नकवी

रविशंकर प्रसाद

रामविलास पासवान (फाइल)

- पीएमओ की ओर से सभी मंत्रियों को भेजा गया है पत्र

झारखंड का प्रभार दिया गया है। नितिन गडकरी और प्रकाश जावडेकर महाराष्ट्र के प्रभारी होंगे। उत्तर प्रदेश का प्रभार राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडेय, संजीव बालियान और कृष्ण पाल गुर्जर को दिया गया है। रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान को बिहार का प्रभार दिया गया है। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान और पंजाब के प्रभारी होंगे।

गरीबों को मिलता रहे भोजन : निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गरीबों को भोजन प्रदान करने वाले सामुदायिक रसोईघरों को कोई परेशानी न हो। इस कदम की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में यह संक्रमण कम्युनिटी फेज में न पहुंचने पाए। इस मामले में अन्य राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को भी विश्वास में लिया गया है।

राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित कर सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रपति उनसे कोरोना महामारी से लड़ने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए कह सकते हैं।

असर

सियासी उबाल वाले बड़े-बड़े मुददे चर्चाओं से हुए गायब, पुराने धुरंधरों के मुताबिक आपातकाल में भी सियासी गतिविधियों पर नहीं था ऐसा लॉकडाउन

कोरोना के कहर में राजनीति भी हो गई 'कैद'

संजय मिश्र, नई दिल्ली

आंधी-तूफानों में भी नहीं ठहरने वाली राजनीति को कोरोना वायरस के कहर ने पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में ला खड़ा किया है। इस महामारी का यह खौफ ही है कि अभी हफ्तेभर पहले तक देश की सियासत को गरमाते रहे बड़े-बड़े मुद्दे चर्चाओं तक से गायब हो गए हैं। चाहे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी का मसला हो या फिर एनपीआर का विवाद या फिर सियासी पाला बदलने से जुड़ा हार्स ट्रेडिंग के आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर सब कुछ कोरोना के कहर में कैद हो गया है। इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पारा आसमान तक पहुंचाने वाली पार्टियों की सियासी जुबान पर भी संपूर्ण लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है।

पुराने राजनीतिक धुरंधरों की मानें तो राजनीति की गति पर ऐसा गंभीर ब्रेक तो शायद आपातकाल के दौर में भी नहीं था क्योंकि तब विपक्षी पार्टियों के नेता गुपचुप अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। समाजवादी पृष्ठभूमि के दो पुराने नेताओं ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि राजनीतिक बंदी का ऐसा दौर तो उन लोगों ने कभी नहीं देखा जैसा कोरोना के कहर से दिखने लगा है। इस महामारी का खौफ ही ऐसा है कि मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े 21 दिन के लॉकडाउन में राजनीतिक पार्टियां अपनी मौजूदा सियासत की मुख्य धुरी बने मुद्दों को भी फिलहाल भूलती दिख रही हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियां बीते तीन-चार महीने से सीएए, एनआरसी व एनपीआर को लेकर राजग सरकार से बड़ी सियासी जंग लड़ रही थीं। मगर कोरोना संकट में ये मुद्दे अब चर्चा से भी बाहर हो गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर को सरकार ने खुद ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

कोरोना संकट के कारण राजनीतिक लॉकडाउन का असर इसी से समझा जा सकता है कि सीएए-एनआरसी के खिलाफ सबसे बड़े विरोध का प्रतीक बन चुके शाहीनबाग के 100 दिनों तक चले विरोध-प्रदर्शन को लॉकडाउन की घोषणा के बाद हटाया गया तो इसकी मुखालफत का कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। वामपंथी दलों के अलावा विपक्षी खेमे की किसी पार्टी की ओर से शाहीनबाग का धरना खत्म करने का विरोध सामने नहीं आया।

कोरोना के चलते राज्यसभा की कुछ सीटों का चुनाव स्थगित हुआ तो विधायकों की खरीद-फरोख्त और तोड़-फोड़ को लेकर 15 दिनों से अधिक गरम रहा यह मुददा अचानक ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना के कहर से राजनीति थमे, उससे पहले ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने आनन-फानन में लॉकडाउन से 24 घंटे पहले शपथ ले ली। मगर शिवराज की कैबिनेट कब बनेगी और कौन लोग मंत्री बनेंगे इसकी फिलहाल न कोई चर्चा है न लोगों की दिलचस्पी। यहां तक की सरकार गिराने वाले कांग्रेस के 22 पूर्व विधायकों को इसके लिए किस तरह का सियासी इनाम मिलेगा इसका भी जिक्र नहीं हो रहा। पांच विधायकों के इस्तीफा देने के बाद टूट के डर से जयपुर में रखे गए गुजरात के कांग्रेस विधायक भी लॉकडाउन से ठीक पहले अपने सूबे लौट गए।

कोरोना ने सियासी मुद्दों पर ही लॉकडाउन नहीं लगाया है बल्कि पार्टियों की सामान्य गतिविधियां भी ठप कर दी हैं। संसद सत्र जहां अचानक स्थगित कर दिया गया, वहीं अमूमन सत्र के आखिर में सहयोगी दलों के नेताओं व सांसदों के लिए होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोज भी इस बार नहीं हुआ।

इसके साथ ही संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी घटक दलों व पार्टी सांसदों के लिए आयोजित किए जाने वाले अपने भोज का खयाल छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो अपने सदस्यता अभियान की गति को भी कोरोना के चलते ब्रेक देना पड़ गया है। इस तरह अधिकांश राजनीतिक गतिविधियों बंद हो गई हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी